



# Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 31-2024] CHANDIGARH, TUESDAY, JULY 30, 2024 (SRAVANA 8, 1946 SAKA)

## PART-I

### Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 जुलाई, 2024

संख्या 2045-व-1-2024 / 3971.—

#### वन मित्र योजना

(समुदाय द्वारा गैर-वन भूमि पर वृक्षारोपण के लिए हरियाणा सरकार की योजना)

#### 1. कार्यकारी सारांश

वन मित्र योजना गैर-वन भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की एक पहल है। स्वस्थ पर्यावरण के लिए हरित आवरण की महत्वपूर्ण भूमिका और हरियाणा में वन क्षेत्रों में कमी के दृष्टिगत, इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में वृक्ष आवरण को बढ़ाने में स्थानीय समुदायों को सीधे शामिल करना है। पूरे राज्य में फैले स्थानीय स्वयंसेवकों के समर्थन का लाभ उठाकर, यह योजना पर्यावरण संरक्षकता की संस्कृति, वृक्षारोपण और उसकी देखभाल के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने की कल्पना करती है। इसके अतिरिक्त, भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जून, 2024 में शुरू किए गए अभियान "एक पेड़ माँ के नाम" के तहत लगाये गये वृक्षों का रख-रखाव, वन मित्र योजना के साथ एकीकृत किया जाएगा।

#### 2. परिचय

पर्यावरणीय स्थिरता भूमि पर हरित आवरण की सीमा पर निर्भर करती है। हरियाणा जैसे कम वन वाले राज्यों में, नागरिकों के लिए पारिस्थितिक संतुलन और परिवेश पर्यावरण की बहाली के लिए निर्दिष्ट वन क्षेत्रों के बाहर वृक्ष आवरण को बढ़ाने की आवश्यकता है। वन मित्र योजना का उद्देश्य सामुदायिक संसाधनों को जुटाना, वृक्षारोपण और उसके उपरान्त उसकी देखभाल के लिए उत्साहित करना है।

#### 3. योजना अवलोकन

(क) उद्देश्य: वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, वृक्षारोपण की सफलता दरों को बढ़ाना और एक जीवन्त पर्यावरण के लिए गैर-वन भूमि पर वृक्ष आवरण को बढ़ाना।

#### (ख) संचालन प्रक्रिया

- सार्वजनिक जागरूकता** : इस योजना को प्रिंट मीडिया और वन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से व्यापक प्रचार दिया जाएगा।
- पात्र परिवारों की पहचान** : 1.8 लाख से कम वार्षिक आय वाले पात्र परिवारों/व्यक्तियों की पहचान, नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) द्वारा बनाए गए परिवार पहचान पत्र (PPP) के आंकड़ों से की जाएगी और योजना में भागीदारी के लिए पात्रता की सूचना दी जाएगी। इस संदेश के माध्यम से हितधारकों को वन मित्र पोर्टल/मोबाइल ऐप पर पंजीकरण प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा।

- iii. **पंजीकरण** : पात्र परिवार के एक सदस्य (आयु 18 से 60 वर्ष के बीच) को वन मित्र मोबाइल पोर्टल/ऐप पर पंजीकृत किया जा सकता है। पंजीकरण के समय लगाए जाने वाले पौधों की संख्या की जानकारी परिवार के सदस्य द्वारा दी जाएगी।
  - iv. **पंजीकृत आवेदकों द्वारा वृक्षारोपण** : वन मित्र पोर्टल पर पंजीकृत सभी आवेदकों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर उनके द्वारा पहचानी गई गैर-वन भूमि पर न्यूनतम 10 और अधिकतम 1000 पौधे लगाने का अवसर दिया जाएगा, जिसे एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। आवेदकों को गैर-वन भूमि की पहचान करनी होगी और गड्ढे खोदने होंगे व जियो-टैग करना होगा और गड्ढे की फोटो वन मित्र ऐप पर अपलोड करनी होगी। सफलतापूर्वक गड्ढे खोदने और वन मित्र पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने के बाद, आवेदक वन विभाग द्वारा संचालित पौधशाला से पौधे प्राप्त कर सकते हैं। वन मित्र पोर्टल/ऐप (<http://164.100.137.122/vanmitra>) और वन विभाग की वेबसाइट (<https://haryana.Forest.gov.in/>) पर पौधे प्राप्त करने के लिए वन पौधशालाओं की सूची उपलब्ध होगी, जिसमें पौधशाला का स्थान और पौधशाला प्रभारी का नाम भी शामिल होगा। आवेदकों द्वारा गड्ढों की खुदाई और वृक्षारोपण, प्रशिक्षण सामग्री में वर्णित निर्दिष्ट गड्ढे के आकार और वृक्षारोपण तकनीकों के अनुसार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सफलतापूर्वक गड्ढे खोदने, जियोटैग करने और वन मित्र पोर्टल पर तस्वीरें अपलोड करने वाले सभी आवेदकों को प्रति गड्ढा 20 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वन नर्सरियों से पौधे प्राप्त करने और उन्हें खोदे गए गड्ढों पर वृक्षारोपण करने, जियोटैग करने और वन मित्र मोबाइल ऐप पर पोर्टल पर तस्वीरें अपलोड करने के बाद, वन मित्रों को प्रति पौधा 30 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जो सीधे उनके खाते में जमा की जाएगी।
  - v. **वन मित्र का चयन** : सभी पंजीकृत आवेदक जो वन मित्र मोबाइल ऐप का उपयोग करके सफलतापूर्वक पेड़ लगाते हैं, जियोटैग करते हैं और उनकी तस्वीरें अपलोड करते हैं, उन्हें 'वन मित्र' की मान्यता दी जाएगी। ये वन मित्र अपने द्वारा लगाए गए पौधों के साथ-साथ अन्य वन मित्रों या 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के प्रतिभागियों द्वारा उन्हें सौंपे गए पौधों के निरंतर रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे। ऐसे वृक्षारोपण के आगामी रखरखाव के लिए, वन मित्र को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया वन मित्र पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।
  - vi. **भूमि की पहचान** : वन मित्र गैर-वन भूमि जैसे कि पंचायत भूमि, संस्थागत भूमि और सरकारी भूमि (जैसे, स्कूल, कॉलेज, औषधालय, सरकारी कार्यालय, जल-घर आदि) के साथ-साथ गाँव के तालाबों, पंचायत भवनों, वृक्षारोपण के लिए शमशान घाट, गैर-अधिसूचित सड़कें आदि का चयन वृक्षारोपण के लिए करेगा।
  - vii. **प्रशिक्षण** : पंजीकृत आवेदकों को वन मित्र पोर्टल और ऐप पर पर्याप्त प्रशिक्षण सामग्री मिलेगी, जिसमें वन मित्र मोबाइल ऐप का उपयोग करना, वृक्षारोपण तकनीक, सुरक्षा उपायों और लगाए गए पौधों की जियोटैगिंग के बारे में जानकारी मिलेगी।
4. **कार्यान्वयन समयरेखा और गतिविधियाँ**
    - (क) **पहले वर्ष**
      - i. फरवरी/मार्च : पंजीकरण, चयन एवं प्रशिक्षण।
      - ii. 15 जुलाई से 31 अगस्त : गड्ढे की खुदाई और वृक्षारोपण के साथ जियोटैगिंग
      - iii. सितम्बर से मार्च : वृक्षारोपण का रखरखाव एवं सुरक्षा।
    - (ख) **दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष**  
वृक्षारोपण का रखरखाव एवं सुरक्षा।
  5. **प्रोत्साहन राशि**
    - (क) **पहले वर्ष**  
**गड्ढे खोदना**
      - i. गड्ढा खोदने व उसकी जियो टैगिंग करके उसका विवरण गड्ढों की फोटो के साथ वन मित्र ऐप पर अपलोड करने के बाद 20 रु0 प्रति गड्ढा की अदायगी।
    - वृक्षारोपण**
      - ii. वृक्षारोपण उपरान्त उसकी जियो टैगिंग करके उसका विवरण पौधों की फोटो के साथ वन मित्र ऐप पर अपलोड करने के बाद 30 रु0 प्रति पौधा की अदायगी।
    - वृक्षारोपण रखरखाव**
      - iii. वन मित्र द्वारा महिने में वृक्षारोपण के रख-रखाव/संरक्षण कार्य उपरान्त पौधों के फोटोग्राफ वन मित्र मोबाइल ऐप पर अपलोड करने के बाद आगामी माह के प्रथम सप्ताह में प्रति जीवित पौधा 10 रुपये का भुगतान।

- (ख) दूसरे वर्ष  
वन मित्र द्वारा महिने में वृक्षारोपण के रख-रखाव/संरक्षण कार्य उपरान्त पौधों के फोटोग्राफ वन मित्र मोबाइल ऐप पर अपलोड करने के बाद आगामी माह के प्रथम सप्ताह में प्रति जीवित पौधा 8 रुपये का भुगतान।
- (ग) तृतीय वर्ष  
वन मित्र द्वारा महिने में वृक्षारोपण के रख-रखाव/संरक्षण कार्य उपरान्त पौधों के फोटोग्राफ वन मित्र मोबाइल ऐप पर अपलोड करने के बाद आगामी माह के प्रथम सप्ताह में प्रति जीवित पौधा 5 रुपये का भुगतान।
- (घ) चौथे वर्ष  
वन मित्र द्वारा महिने में वृक्षारोपण के रख-रखाव/संरक्षण कार्य उपरान्त पौधों के फोटोग्राफ वन मित्र मोबाइल ऐप पर अपलोड करने के बाद आगामी माह के प्रथम सप्ताह में प्रति जीवित पौधा 3 रुपये का भुगतान।
6. तकनीकी एकीकरण
- (क) वन मित्र ऐप : पंजीकरण, जियो-टैगिंग और वृक्षारोपण की सफलता की जांच के लिए।
- (ख) प्रोत्साहन राशि का भुगतान : सरकार की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डायरेक्ट बनेफिट ट्रांसफर) (डीबीटी) नीति का पालन करते हुए वन मित्रों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे उनके खातों में किया जाएगा।
7. योजना के बुनियादी कार्यान्वयन दिशानिर्देश
- (क) प्रजाति चयन : योजना के तहत केवल देशी एवं बहुउद्देशीय प्रजाति के वृक्ष ही लगाये जायेंगे। लगाए जाने वाले पौधों में छोटी अवधि वाली प्रजातियां यूकेलिप्टस और पोपलर, जिनका उपयोग आमतौर पर कृषि-वानिकी में किया जाता है, शामिल नहीं होंगी।
- (ख) पौधे से पौधे की दूरी : पौधे से पौधे की न्यूनतम दूरी लगभग आठ मीटर होगी। इस दूरी से प्रति एकड़ लगभग 65 पौधे लगाए जा सकते हैं।
- (ग) गैर-स्वामित्व वाली भूमि पर वृक्षारोपण : यदि वन मित्र से संबंधित भूमि पर वृक्षारोपण नहीं किया गया है, तो वह भूमि के मालिक को वृक्षारोपण के चार साल पूरे होने के बाद पौधों को भूमि के मालिक को सौंप देगा और मालिक फिर पौधे की उसकी संपत्ति के तौर पर देखभाल करेगा। प्रत्येक सौंपे गए पौधे के लिए वन मित्र को प्रति पौधा 25 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। यदि रोपा गया पेड़ स्वयं वन मित्र की भूमि पर है, तो उसे पेड़ का मालिक माना जाएगा और इसके बाद उसे पेड़ के मालिक के रूप में योजना अनुसार प्रोत्साहन राशि देय होगी।
8. वन मित्र की भूमिका एवं जिम्मेदारी
- (क) गैर-स्वामित्व वाली भूमि के लिए सहमति : यदि वृक्षारोपण के लिए चिन्हित भूमि वन मित्र के स्वामित्व में नहीं है, तो वह मालिक/अधिकृत व्यक्ति से लिखित में सहमति प्राप्त करेगा।
- (ख) वृक्षारोपण और देखभाल : मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) में निहित विनिर्देशों के अनुसार, वृक्षारोपण के लिए आवश्यक गड्ढे खोदना और इसके बाद गड्ढे में वृक्षारोपण करना और उनकी देखभाल करना।
- (ग) जियोटैगिंग और अपलोडिंग : गड्ढे की खुदाई, पौधारोपण, पौधों के मासिक रखरखाव/सुरक्षा उपरान्त प्रत्येक गड्ढे/पौधे की जियोटैगिंग और तस्वीरें अपलोड करना। यदि वन मित्र द्वारा दावा किया गया कार्य, 10% से अधिक झूठा पाया जाता है, तो वन मित्र को हटा दिया जाएगा।
- (घ) पौधों की सफलता : वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित करना।
- (ङ) 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान : हरियाणा का कोई भी निवासी 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगा सकता है और उसे आगे की देखभाल के लिए संबंधित वन मित्र को सौंप सकता है। इसके बाद, वन मित्र उक्त पेड़ के रखरखाव के लिए जिम्मेवार होंगे और पैरा 5 क (iii) के अनुसार प्रोत्साहन राशि के हकदार होंगे।
9. वन विभाग की भूमिका एवं जिम्मेदारी
- (क) नियंत्रण/पर्यवेक्षी अधिकारी : कार्य के निष्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए संबंधित वन रक्षक नियंत्रण अधिकारी होंगे और संबंधित ब्लॉक/रेंज अधिकारी वन मित्र के पर्यवेक्षी अधिकारी होंगे। वे वन मित्र की अपलोड की गई रिपोर्ट का मूल्यांकन भी करेंगे।
- (ख) पौधों की आपूर्ति : वृक्षारोपण के लिए आवश्यक स्वस्थ पौधे उपलब्ध कराना, जिसमें 10% अतिरिक्त पौधे वृक्षारोपण के दौरान मरे पौधों को दोबारा रोपित करने के लिए होंगे।
- (ग) प्रशिक्षण : वन मित्रों को बुनियादी प्रशिक्षण देने के लिए, पर्याप्त प्रशिक्षण सामग्री प्रदान की जाएगी, जिसमें वृक्षारोपण की तकनीक, रखरखाव/संरक्षण, लगाए गए पौधों की जियोटैगिंग ईत्यादि शामिल हैं। मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) में पौधारोपण तकनीक, पौधों की निराई, गुड़ाई, सिंचाई और पौधों को पाले से बचाने के उपायों की आवश्यकताएं शामिल होंगी। यदि आवश्यक हुआ, तो वन मित्रों को वन मित्र मोबाइल ऐप पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्राप्त होगा।

- (घ) **सलाहकारी सहायता** : वन रक्षक, वनपाल और रेंज अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर वन मित्रों को वृक्षारोपण के संबंध में सलाह प्रदान करेंगे।
- (ङ) **वन मित्र का विघटन** : कदाचार/दुर्व्यवहार या असंतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर वन मित्र को हटाया जा सकता है। वन मित्र को राज्य सरकार के नियमित सरकारी कर्मचारी के रूप में नियमितीकरण/समावेश/नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- (च) **दस्तावेजीकरण** : वन मित्र द्वारा किये गये वृक्षारोपण की सफलता प्रतिशत के आकलन का दस्तावेजीकरण।

आनंद मोहन शरण,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

## HARYANA GOVERNMENT

### ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE DEPARTMENT

#### Notification

The 19th July, 2024

No. 2045-Ft-1-2024/3971.—

#### Van Mitra Scheme

[Haryana Government scheme for plantation by community on non-forest land]

#### 1. Executive Summary

The Van Mitra scheme is an initiative by the government to encourage community participation in tree plantation activities on non-forest lands. Recognizing the critical role of green cover for a healthy environment and the shortfall in forest areas in Haryana, this scheme aims to involve local communities directly in enhancing tree cover across the state. By leveraging the support of local volunteers spread all over the State, the scheme envisions fostering a culture of environmental guardianship and personal commitment towards tree planting and care. The maintenance of tree planted under “**Ek Ped Maa Ke Naam**” campaign launched by Hon'ble Prime Minister of India in June, 2024 shall be integrated with Van Mitra Scheme.

#### 2. Introduction

Environmental sustainability depends on the extent of green cover on the land. In forest-deficit states like Haryana, the need is to increase tree cover outside designated forest areas for the restoration of ecological balance and ambient environment for the citizens. The Van Mitra scheme represents a strategic intervention aimed at mobilizing community resources and inculcating enthusiasm for tree plantation and aftercare of plantations.

#### 3. Scheme Overview

- a. **Objective:** To promote community participation in tree plantation, ensuring increased survival rates of plantations and enhancing tree cover on non-forest land for a healthier living environment.
- b. **Operational Procedure**
  - i. **Public Awareness:** The scheme will be given large publicity through print media and the website of the forest department.
  - ii. **Identification of Eligible Families:** The eligible families/persons having an annual income of less than 1.8 lakh will be identified from data of Parivar Pehchan Patra (PPP) maintained by the Citizens Resources Information Department (CRID) and intimation of eligibility for participation in the scheme will be given to the families through various measures. Through this message, the stakeholders will be made aware of the process of registration on the Van Mitra portal/ mobile app. of the scheme.
  - iii. **Registration:** The eligible families will register one eligible member (age between 18 to 60 years) of the family on Van Mitra Portal/app. The information on the number of saplings to be planted will be given at the time of registration by the family member.
  - iv. **Plantation by registered applicants:** All registered applicants on the Van Mitra portal shall be given opportunity to plant minimum of 10 and upto 1000 saplings on non-forest land identified by them within a designated timeframe, which will be communicated via SMS. The applicants shall identify non-forest land and dig pits, geo-tag and upload pit photo on the Van Mitra App. After successfully digging pits and uploading information on Van Mitra Portal, the applicants

can collect saplings from designated nurseries operated by the Forest Department. The Van Mitra portal/App (<http://164.100.137.122/vanmitra>) and the Forest Department's website (<https://haryanaforest.gov.in/>) will provide a comprehensive list of these nurseries, including their locations and the names of the nursery in-charges. The digging of pits and plantation by the applicants, shall be carried out according to the specified pit size and plantation techniques detailed in the training material. Additionally, all applicants who successfully dig pits, geotag and upload photographs on Van Mitra portal will be given incentive of Rs.20 per pit. After collection of plants from forest nurseries and planting them on the dug up pits, geotag and upload photographs on the portal on Van Mitra Mobile app, The Van Mitras shall receive incentive of Rs.30 per plant, directly credited to their account.

- v. **Selection of Van Mitra:** All registered applicants who successfully plant trees, geotag and upload photographs of them using the Van Mitra mobile app will be recognised as “**Van Mitra**”. These Van Mitras will be responsible for the ongoing maintenance of the saplings they have planted, as well as those handed over to them by other, Van Mitras, or participants of the '**Ek Ped Maa Ke Naam**' campaign. The transfer of such plantations for subsequent maintenance to the Van Mitra will be conducted online through the Van Mitra portal.
- vi. **Land Identification:** The Van Mitra will identify and arrange non-forest lands such as Panchayat land, institutional land, and government land (e.g., schools, colleges, dispensaries, government offices, water-works etc.), as well as village ponds, panchayat buildings, shamshaan ghaats, non-notified roads etc. for plantation.
- vii. **Training:** Registered applicants will have access to comprehensive training materials on the Van Mitra portal and app. These resources will cover plantation techniques, protection measures, and the geotagging of planted saplings using the Van Mitra mobile app.

#### 4. Implementation Timeline and Activities

##### a. 1st Year

- i. **February/March:** Registration, selection and training.
- ii. **July 15th to August 31st:** Pit digging and Plantation along with geotagging.
- iii. **September to March:** Maintenance and protection of plantation.

##### b. 2nd, 3rd and 4th Year

Maintenance and protection of plantation.

#### 5. Incentives:

##### a. 1st Year

###### Digging of pits

- i. **Rs.20 per dug up pit** after geo-tagging and uploading the photograph of the pits dug by Van Mitra on the Van Mitra Mobile app.

###### Plantation

- ii. **Rs. 30 per planted sapling** after geo-tagging and uploading photographs of the saplings planted by the Van Mitra on the Van Mitra mobile app.

###### Plantation Maintenance

- iii. **Rs. 10 per surviving sapling**, in the first week of every following month of maintenance/ protection works of the plantation and uploading of photographs of plants on the Van Mitra mobile app by Van Mitra.

##### b. 2nd Year

**Rs. 8 per surviving sapling** in the first week of every following month of maintenance/ protection works of the plantation and uploading of photographs of plants on the Van Mitra mobile app by Van Mitra.

##### c. 3rd Year

**Rs. 5 per surviving sapling** in the first week of every following month of maintenance/ protection works of the plantation and uploading of photographs of plants on the Van Mitra mobile app by Van Mitra.

##### d. 4th Year

**Rs. 3 per surviving sapling** in the first week of every following month of maintenance/ protection works of the plantation and uploading of photographs of plants on the Van Mitra mobile app by Van Mitra.

## 6. Technology Integration

- a. **Van Mitra App:** For registration, geo-tagging and assessment of the survival of plantations.
- b. **Payment of Incentive:** Payment of incentive to Van Mitras will be made directly into their accounts, adhering to the government's Direct Transfer Benefit (DBT) policy of Government.

## 7. Basic implementation guidelines of Scheme

- a. **Species Selection:** Under the scheme, only native and multipurpose tree species shall be planted. Saplings to be planted will not include short-rotation species such as eucalyptus and poplar, which are typically used in agro-forestry.
- b. **Plant-to-Plant Distance:** The minimum plant-to-plant distance will be around eight meters. With this spacing, about 65 plants per acre can be planted.
- c. **Plantation on Non-Owned Land:** In case the plantation is done on land not belonging to Van Mitra, he will hand over the plants to the owner of the land after completion of four years of plantation to the owner of the land and the owner will then take care of the plant as his property. An honorarium of Rs. 25 per handed-over plant will be given to the Van Mitra. In case the planted tree is on the land of Van Mitra himself, he will be deemed to be the owner of the tree and further incentives hereinafter will be admissible to him as the owner of the tree.

## 8. Role and responsibility of Van Mitra

- a. **Consent for Non-Owned Land:** In case the land identified for the plantation is not in the ownership of Van Mitra, he will obtain consent from the owner/authorised person in writing.
- b. **Plantation and Care:** To dig pits required for plantations and further carry out plantations in the pit and take their care as per specifications contained in the Standard Operating Procedures (SOPs).
- c. **Geotagging and Uploading:** To geotag and upload photographs of each pit/sapling after completing activities such as pit digging, sapling plantation, monthly maintenance/protection of plants and to provide number of surviving plants using the Van Mitra App. If more than 10% of claimed work is found to be false, Van Mitra shall be disengaged.
- d. **Survival of Plants:** To ensure good survival of plantations.
- e. **'Ek Ped Maa Ke Naam' Campaign:** Any resident of Haryana can plant a tree under the campaign 'Ek Ped Maa Ke Naam' in the name of his/her mother and hand it over to the concerned Van Mitra for further maintenance. Subsequently, the Van Mitra will be responsible for the maintenance of the said tree and will be entitled to incentives as per para 5a (iii).

## 9. Role and responsibility of the Forest Department

- (a) **Controlling/Supervisory Officers:** The concerned forest guard shall be the controlling officer and concerned Block /Range officers shall be the supervisory officers of Van Mitra for facilitating the execution of work. They shall also evaluate and assess the uploaded reports of Van Mitra.
- (b) **Supply of Saplings:** To provide healthy saplings for the plantation and to beat up mortality of saplings (10%) to the Van Mitra.
- (c) **Training:** To impart basic training to Van Mitras, training materials will be provided covering techniques of plantation, maintenance/protection, geotagging of planted saplings, and the preparation of Standard Operating Procedures (SOPs) such as requirements for weeding, hoeing, irrigation, and measures for protecting plants from frost. If required, Van Mitras will also receive hands-on training on the Van Mitra mobile app.
- (d) **Advisory Support:** The forest guards, foresters and range officers will provide advice concerning plantation to Van Mitras within their area of jurisdiction as and when required by them.
- (e) **Disengagement of Van Mitra:** The engagement of Van Mitra may be discontinued on the grounds of misconduct/misbehaviour, or unsatisfactory performance. The Van Mitra shall have no right to claim regularisation/absorption/appointment as a regular government employee of the state government.
- (f) **Documentation:** Documentation of assessment of survival percentage of plantation done by Van Mitra.

ANAND MOHAN SHARAN,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Environment, Forests and Wildlife Department.